(c) The assessments have been made bringing to tax the income of M/s. Tobacco Board on the ground that it has a separate corporate existence.

(d) and (e) The attachment on the current accounts in all the banks has been lifted. Even the deposits that have matured upto 15-12-1993 have also been released.

SETTING UP OF SPECIAL BANK BRANCHES FOR S. S. I.

2607. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to direct the banks to open special branches catering to small scale industries (SSIs), if so, the details thereof;

(b) how many branches of various banks are supposed to be opened up and at what centres in India and details therof;

(c) what are the recommendations of the Nair Committee on SSIs; and

(d) whether Government accepted all the recommendations, if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) Under the liberalised policy of Reserve Bank of India (RBI), commercial banks can take decision of their own without the perior approval of RBI for opening of industrial finance, overseas/small scale industry (SSI) branches. RBI has also advised commercial banks to open specialised branches to cater to the SSI clientele in the 45 Districts where there are more than 2000 SSI units. After a suitable interval of time, the process of opening specialised branches on priority basis in another 119 Districts each with more than 1,000 and upto 1,999 SSI units will be initiated.

(c) and (d) Hon'ble Member is presumably, referring to Nayak Committee on SSI financing. One of the recommendations of the Committee is that to discharge their responsibility under the single window scheme, the commercial banks should open specialised branches to cater to the SSI clientele. As already stated above in parts (a) & (b), the banks have been authorised to open branches without prior approval of RBI.

अल्पसंख्यकों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां

2608. श्री मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अल्पसंख्यकों को सरकार के कल्याण कार्यक्रमों में शामिल योजनाओं के अंतर्गत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई मामलों में तो उनको ऋण ही नहीं मिल पाता है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे सरकार के कई कल्याण कार्यक्रमों और बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण का सुचारू और पर्याप्त ऋण का प्रवाह प्रदान करने के लिए कई कदम उठाये। फिर भी जब कभी अल्पसंख्यक समुदायों सहित जनता से इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त होती है जिसमें ऋण मंजूर करने या बैंक ऋण प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का जिक्र किया गया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा वह शिकायत संबद्ध बैंक के साथ उठाई जाती है। इसके अतिरिक्त बैंकों के कर्मचारियों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी

अनुसूचित भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को नवम्बर 1987 में जारी किए गए अपने पहले के निर्देशों को अगस्त 1993 में दोहराते हुए कहा है कि बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित सभी संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग के रूप में लैक्चर के उपयुक्त सत्र, प्राथमिकता क्षेत्र का वित्तपोषण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि शामिल करने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय बहुल वाले पता लगाए गए 41 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के ऋणकर्ता खातों की संख्या मार्च, 1990 में 12.25 लाख थी। यह संख्या मार्च 1993 में बढ़कर 13.60 लाख हो गई। इन अल्पसंख्यक समुदाय बहुल वाले पता लगाए गए 41 जिलों में इसी अवधि के दौरान बकाया राशियां 721 करोड़ रुपए बढ़कर 952 करोड़ रुपए हो गई। देश के भी जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण भी मार्च 1990 में 4,332 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 1993 में 5,675 करोड़ रुपए हो गया। अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण कर्ता खातों की संख्या भी मार्च 1990 में 53 लाख से बढ़कर मार्च 1993 में 57 लाख हो गई।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जन प्रतिनिधियों के पदों की रिक्तियां

2609. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धन में निर्वाचित/नाम-निर्देशित किए जाने वाले जन-प्रतिनिधियों के कई पद काफी समय से रिक्त हैं जिससे जन-प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में, प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक-बोर्ड में नौ गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। इस समय 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के 85 पद खाली पड़े हैं। सरकार ने इन खाली पदों को भरने के लिए पहले ही आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

POOR PERFORMANCE OF PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

2610. PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) on what basis did the Finance Minister exonerate Managements of Public Undertakings from the responsibility for poor functioning of P.S.Us;

(b) when he blames political interferences besides lack of work culture, what part of the management is the product of political interference;

(c) how the Management can be exonerated from the responsibility for the ills of P.S.Us; and

(d) whether lack of work culture concerns workers and it is not anti-workers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) to (d) The unsatisfactory performance of a number of public sector undertakings (PSUs) is due to a variety of factors such as huge cost and time over-runs in project implementation, adverse locational and investment decisions in some sectors and implicit low return for reasons of high risk involved for supply of basic infrastructural goods and services. Government has since undertaken a number of reforms in the public sector. These reforms include, inter-alia, phasing out of Budgetary support in the form of non-plan loans to loss-making enterprises; disinvestment upto 49 per cent in select profit making enterprises for mobilising non-inflationary resources for the Budget, as also for broad basing ownership and creating a greater commercial ori-